पाठक मंच

युवा वर्ग का भविष्य

कहा जाता है, कि युवा ही देश का भविष्य है। जिस प्रकार एक माली अपने बाग की हमेशा देखभाल करता रहता है, ठीक उसी प्रकार आज का युवा ही देश अथवा समाज का माली है। किन्तु आज समाज में ऐसे युवाओं की कमी है। आज सारे देश और समाज में तबाही मची हुई है, और मध्य वर्ग के युवा गरीबों के बारे में नहीं सोचते बल्कि अपने स्वार्थ के लिए अपने कैरियर के पीछे पड़े हैं। युवाओं को उनके बारे में सोचने का भी समय नहीं है। समझ में नही आता इन्हें क्या कहूँ। इन्हें तो युवा कहना ही गलत है। युवा तो वही है जो दूसरों के लिए अपनी सारी जिन्दगी दाँव पर लगा दे, जो हमेशा मजदूरों किसानों के लिए सोचे। यही सच्चे युवा की पहचान है। इन्हें ही युवा कहा जा सकता है। अगर कोई भी गरीब आदमी किसी सरकारी दफ्तर में जाता है तो बिना दर्जनों चक्कर लगाए और कुछ 'भेंट' के बिना काम नहीं होता है। ये सरकारी नौकरीयाँ मानों एक ही आवें के बर्तन हैं। जो भी उस आवें से निकलता है, या तो वह जला हुआ ही निकलता है, गलती से अगर कोई सही निकला तो वह भी जल्द ही उसी रंग मे रंग जाता है, अगर फिर भी कोई बच गया तो इस समाज की पुलिस की मार से परेशान होकर वो भी वही काम करने लगता है। इस समाज को नर्क बना दिया गया है। नेता, पूँजीपति और चोर, मुनाफाखोर समाज में भ्रष्टाचार फैलाने का काम करते हैं। आज देश की राजनीति इतनी दूषित हो चुकी है कि कोई भी शरीफ आदमी इसमें प्रवेश कर नहीं सकता। दूसरे, पूँजीपति जो लाखों-करोड़ों रुपया नेताओं को देकर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हैं। और इनके साथ पुलिस और प्रशासन मिलकर एक से बढ़ कर एक अपराध करते हैं। और नाम गरीब आदमी का लग जाता है। हम मानते हैं कि अब युवा ही देश को व्यवस्था बदलकर बचा सकते हैं। और इसके लिए सभी युवाओं को एकत्र होना पड़ेगा और फिर क्रान्ति करनी पड़ेगी। इस लिए हम उन युवाओं का आह्वान करते हैं कि गरीबों की रोटी के लिए संघर्ष करें।

- शैलेन्द्र कुमार
989, कटरा मनमोहन पार्क
इलाहाबाद

पैसा

पैसा
सिर्फ पैसा
पैसे से कमाना है
ढेर सारा पैसा
पैसे पर टिका है
समूचा समाज
इसलिए पूजा जाता है
पैसा आज।
आदमी को आदमी नहीं समझता वह
जिसे लगी हो भूख पैसे की,
ईमानदारी और समझदारी की
कीमत ही क्या है
जब लगी हो भूख पैसे की!

सवार हो जाए सिर पर तो
आदमी बन जाता है इसका गुलाम
फिर...
नचाता है आदमी को पैसा
कठपुतलियों की तरह उंगलियों पर।
मुस्कान, अरमान और सारे सपने
सब कुछ तो बिक रहा है...
आखिर क्यों है यह समाज ऐसा
जहाँ आदमी बाद में
पहले है पैसा।

-टोनी, सोनीपत

प्रिय बन्धु,

पहली बार लिख रहा हूँ, इसलिए कुछ औपचारिक बातें अपने बारे में--मैं इस वर्ष तक बी.एच.यू. में एम.ए.(हिन्दी पत्रकारिता) का छात्र बना रहा। आपकी पत्रिका से परिचित होने का अवसर वहीं मिला। कुछ वजहों के चलते मैं परीक्षा न दे सका। नतीजतन, पिछले मार्च से मानसिक अराजकता झेलता रहा और टूटता रहा।

फिर सोचा--नहीं! अपना कीमती जीवन मैं इस तरह नष्ट नहीं होने दूँगा और मैं लड़ूँगा, जूझूँगा, संघर्ष करूँगा, खुद के लिए नहीं बल्कि तमाम बेबस-बेसहारा लोगों के लिए जिनका दुख मुझसे कई गुना ज्यादा है।

मैंने खुद को संभाला और कुछ मित्रों से विचार-विमर्श कर एक संगठन तैयार करने की ठानी। साथ ही, एक पत्रिका 'मशाल' नाम से निकालने की योजना बनी।

प्रयास है कि जल्दी ही प्रवेशांक आ जाए। मैंने लू शुन, गोर्की, चेखव, मार्क्स, लेनिन, और बाल्जाक को जमकर पढ़ा। आज भी कितने प्रासंगिक हैं ये लेखक।

अनुपम निशांत
सम्पादक, 'मशाल'
एफ-37/23, सीमेण्ट फैक्ट्री,
चुनार
मीरजापुर - 231311

प्रिय बन्धु,

मैं आपके द्वारा शहीदे-आजम भगत सिंह और उनके विचारों को प्रसारित

(पेज 10 पर जारी)

एक अपील

'आह्वान कैम्पस टाइम्स' सारे देश में चल रहे वैकल्पिक मीडिया के प्रयासों की एक कड़ी है। हम सत्ता प्रतिष्ठानों, फण्डिंग एजेंसियों, पूँजीवादी घरानों एवं चुनावी राजनीतिक दलों से किसी भी रूप में आर्थिक सहयोग लेना घोर अनर्थकारी मानते हैं। जनता का वैकल्पिक मीडिया सिर्फ जन संसाधनों के बूते खड़ा किया जाना चाहिए--हमारी यह दृढ़ मान्यता है।

अत: हम अपने सभी पाठकों-शुभचिन्तकों-सहयोगियों से अपील करते हैं कि वे अपनी ओर से अधिकतम सम्भव आर्थिक सहयोग भेजकर परिवर्तन के इस हथियार को मजबूती प्रदान करें।!

सामयिकी

यू. पी. ए. सरकार द्वारा पोटा के स्थान पर नया आतंकवाद-विरोधी अध्यादेश लाने का एलान

लुटेरों की नयी मैनेजिंग कमेटी भी जनशक्ति से भयाक्रान्त

● प्रसेन

तमाम धर्मनिरपेक्ष और जनवादी बुद्धिजीवियों में उस समय खुशी की लहर दौड़ गयी थी जब इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में वामपंथी दलों और तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के **संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)** सरकार का गठन हुआ। इसमें से अधिकांश ऐसे थे जो कांग्रेस और संसदीय वामपंथी दलों को फरिश्तों की पार्टी नहीं मानते हैं। लेकिन उनका तर्क था कि फिलहाल साम्प्रदायिक फासीवादी खतरे को टालने के लिए 'कम शैतान' (लेसर इविल) का चुनाव करने में ही बेहतरी है। इन लोगों को खास खुशी तब हुई जब पोटा रद्द हुआ। लेकिन इसकी खुशी के नशे में वे ऐसा चूर हुए कि संप्रग सरकार को गुपचुप तरीके से अपने इरादे जाहिर करने का मौका मिल गया। अभी संप्रग सरकार का गठन हुए आधा साल भी पूरा नहीं हुआ था कि "आतंकवाद" का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाने के बहाने से पोटा की खाली जगह भरने वाला कानून लाने की घोषणा कर दी गई। सितम्बर में सरकार ने घोषणा की कि वह एक अध्यादेश लाकर **गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून** 1967 में संशोधन करेगी। प्रस्तावित संशोधन में 'आंतकवाद' शब्द को पुन: परिभाषित और विस्तारित किया जाएगा और राष्ट्रविरोधी (?) गतिविधियों में शामिल लोगों को मौत तक की सजा देने का प्रावधान किये जाने की घोषणा की गयी थी। नतीजतन, सरकार ने अगले ही महीने गैरकानूनी गतिविधियाँ निरोधक (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित कर दिया। गौरतलब है कि इस नए अध्यादेश में पोटा के कई प्रावधानों को शामिल किया गया है। इतिहास गवाह है कि राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर आज तक जितने कानून आए हैं वे अपने पूर्वजों से ज्यादा दमनकारी रहे हैं। पूँजीवादी व्यवस्था जैसे-जैसे अपने सभी "कल्याणकारी" मुखौटों को उतार रही है वैसे-वैसे उसे जनविद्रोह से निपटने के लिए अपने आपको अधिक से अधिक चाक-चौबन्द करने की जरूरत महसूस हो रही है। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती कानून टाडा में गिरफ्तार 76000 लागों में से सिर्फ 1 प्रतिशत सजा पाने योग्य पाए गए। मगर टाडा के खत्म होने के बाद भी हजारों लोग जेलों में सड़ रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी पोटा की भी रही। कश्मीर में पोटा सबसे पहले लागू हुआ। पी. डी. पी. की सरकार ने आते ही इसे हटाने का ढोंग रचा। मगर दो साल बीत जाने के बाद भी पोटा के तहत बन्द लोगों को रिहाई नहीं मिली। जो रिहा हुए वे संसदीय लुटेरों की जमात के लोग ही थे। बाकी रिहा लोगों को 'जनसुरक्षा अधिनियम' के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। नए सूचना प्रसारण मंत्री जयपाल रेड्डी ने साफ किया है कि पोटा के तहत चल रहे मुकदमे अपने आप रद्द नहीं होंगे और जिनको पोटा के तहत सजा मुकर्रर हो चुकी है वह कायम रहेगी। साफ है कि पोटा को हटाना एक ढोंग है। पोटा हट जाएगा तो कोई नया सोंटा शोषकों के हाथ में आ जाएगा। इस भ्रम से सभी जनपक्षधर शक्तियों को मुक्त हो जाना चाहिए कि संसदीय नामधारी वामपंथीयों के होने की वजह से, या किसी भी और वजह से संयुक्त प्रगतिशील (?) गठबंधन सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार से कम दमनकारी होगी। उल्टे कोई वजह नहीं दिखती कि ऐसा न हो।

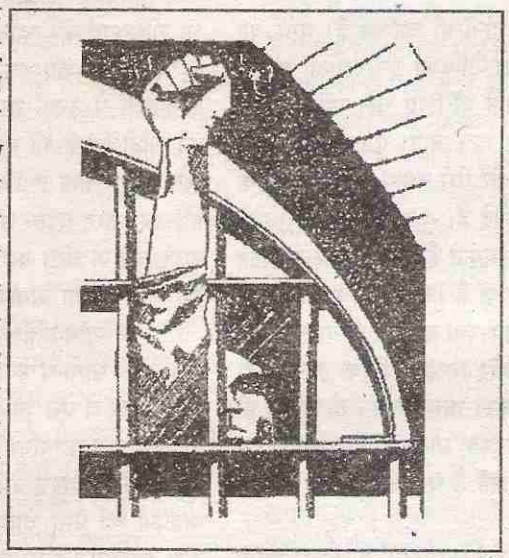

पाठक मंच

(पेज 4 से जारी)

करने की जो मुहिम आप चला रहे हैं मैं उससे प्रभावित हूँ और उससे जुड़ना चाहता हूँ। मैं अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक संगठन बना कर समाज-सेवा के लिए कुछ काम कर रहा हूँ। अगर जयपुर में आपके संगठन की कोई शाखा कार्यरत हो तो मुझे सूचित करें।

अनुराग सिंह खंगारोत, बी-80/7, नित्यानन्दनगर, गांधी पथ, क्वीन्स रोड, जयपुर - 302021

प्रिय सम्पादक महोदय,

प्रथम बार मैंने आह्वान पढ़ा तो लगा कि हम कितने स्वार्थगत भावनाओं से ग्रस्त हैं, हमें सिर्फ अपने स्वार्थों की संकीर्ण चिन्ता रहती है। इन्हीं संकीर्णताओं की वजह से देश का राजनैतिक जीवन अंधकारमय होता जा रहा है। ऐसे में आह्वान एक सूर्य की तरह दिखता है। चन्दन का आत्मदाह, उत्तरांचल में फूटते छात्र आन्दोलन पढ़कर पता चला कि सबकुछ शांत नहीं है। हमें अपने प्रयास जारी रखने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ एक शोषणमुक्त स्वच्छ वातावरण में साँस ले सकें।

दीपेन्द्र प्रताप सिंह, 79, हिन्दू छात्रावास